

प्रेषक,

निदेशक, मत्स्य,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

1- समस्त उप निदेशक, मत्स्य
उत्तर प्रदेश।2- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-

/स्था०शा०/कोर्टकेस/लीगल वेब पोर्टल

दिनांक-

23/8/2022

विषय- विभागीय वेब पोर्टल <http://fymis.upsdc.gov.in> के Legal Monitoring System मॉड्यूल पर
वाद सम्बन्धी विवरण/सूचनाओं की प्रविष्टि एवं उन्हें अद्यतन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयांकित निदेशालय पत्र संख्या-1610/स्था०शा०/कोर्टकेस दिनांक 29.06.2020, पत्र संख्या-3707/स्था०शा०/कोर्टकेस दिनांक 01.10.2020 एवं तत्कम में पुनः प्रेषित पत्र संख्या-3707/स्था०शा०/कोर्टकेस दिनांक 01.10.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभागीय वेब पोर्टल (मुख्य यू०आर०एल०-<http://fymis.upsdc.gov.in>) के अन्तर्गत विकसित Legal Monitoring System मॉड्यूल पर सम्बन्धित मण्डलीय/जनपदीय कार्यालय द्वारा अपने मण्डल/जनपद से सम्बन्धित विभिन्न वादों की पूर्ण विवरण/सूचना प्रविष्टि करते हुये अग्रतर आने वाली सूचनाओं को अद्यतन करने एवं उक्त आधार पर मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने का कार्य अभियान चलाकर सुनिश्चित करने सम्बन्धी निरन्तर विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि उक्त पत्रों द्वारा पूर्व में समय-समय पर प्रकरण में स्पष्ट एवं कड़े निर्देश जारी किये जा चुकने के पश्चात भी आपके स्तर पर उक्त कार्य में प्रगति नहीं हो रही है, फलस्वरूप में विभाग से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों में दाखिल होने वाले, विचाराधीन एवं निस्तारित वादों के विभागीय Legal Monitoring System मॉड्यूल के माध्यम से अनुश्रवण का कार्य प्रारम्भ किया जाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है, जो विभागीय मुकदमों में अपेक्षित कार्यवाहियों को ससमय पूर्ण कराये जाने एवं उनके सम्यक् अनुश्रवण हेतु शासकीय हित में उचित नहीं है।

उक्त संदर्भ में विभागीय समीक्षा बैठकों के दौरान भी निदेशालय स्तर से आपको अगवत कराया गया है तथा ज्ञातव्य को कि तदनुसार उक्त स्थिति की विभागीय समीक्षा बैठकों में निरन्तर समीक्षा/अनुश्रवण किया जायेगा। अतः उक्त संदर्भ में पुनः अपेक्षा की जाती है कि कृपया निदेशालय के उक्त पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर अभियान चला कर अपने मण्डल/जनपद से सम्बन्धित विभिन्न वादों की प्रश्नगत Legal Module पर प्रविष्टियां पूर्ण कराने, तथा नई सूचनाओं को अद्यतन करने का कार्य प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, ताकि आगामी माह से उक्त Legal Module के माध्यम से मा० न्यायालयों में लम्बित, निस्तारित एवं प्राप्त होने वाले वादों की सूचना प्राप्त की जा सके एवं अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा सके। उक्त कार्य में सुगमता एवं एकरूपता हेतु पोर्टल पर निदेशालय स्तर से कतिपय वादों की पूर्ण प्रविष्टियों की सूची मार्गदर्शक सैम्पल-रिपोर्ट के रूप में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

Signed by Puneet Kumar

Date: 22-08-2022 18:38:06

Reason: Approved

(पुनीत कुमार)

उप निदेशक मत्स्य (मुख्यालय)

कृते निदेशक मत्स्य, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्र संख्या-

2837

/स्था०शा०/कोर्ट केस

दिनांक-उक्त।

प्रतिलिपि विशेष सचिव, मत्स्य विभाग, उ० प्र० शासन, सचिवालय लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- उप निदेशक मत्स्य, सहकारिता/सहायक निदेशक मत्स्य (सामान्य शाखा), मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संदर्भ में उपरोक्त पत्र दिनांक 29.06.2020 एवं पत्र दिनांक 01.10.2020 के अनुपालन में आपके नियंत्रणाधीन शाखा से संबंधित वादों के संदर्भ में यथा निर्देशित उपरोक्त कार्य व्यक्तिगत ध्यान देकर सुनिश्चित कराये।

3- ✓ वेब आफिसर, मुख्यालय को विभाग की वेबसाइट पर उक्त पत्र की प्रति अपलोड करने हेतु।



3488/EST

विधिक सूचना प्रणाली

उत्तर प्रदेश सरकार

मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश

बाद की सूची
रिपोर्ट मापदंड—
जिला: GHAZIAPUR

क्र.सं.	बाद संख्या	वारी	प्रतिवासी	वर्ष	न्यायालय	बाद का प्रकार	विषय	गण्य पत्र दिनांक	बाद का विवरण	विचारणीय	बाद की स्थिति
1	विशेष अपील (डिफेंसिव) 38 0/2021	उ0प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग उ0प्र0 शालन, मन्त्रिबालय लखनऊ, 2- निदेशक, मत्स्य विभाग,	देवेन्द्र नाथ राय	2021	मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद	विशेष अपील (डिफेंसिव)	श्री देवेन्द्र नाथ राय, मेवा निवृत्त मत्स्य प्रभार सहायक, कार्यालय मत्स्य पालक विकास अभिकरण, गाजीपुर द्वारा अभिकरण गाजीपुर के मेवा निवृत्त कार्मिक के रूप में प्रस्तुत ग्रेजुटी के मुपतान के दावे के सम्बन्ध		गन्ती श्री देवेन्द्र नाथ राय, मेवा निवृत्त मत्स्य प्रभार सहायक, कार्यालय मत्स्य पालक विकास अभिकरण, गाजीपुर द्वारा अभिकरण गाजीपुर के मेवा निवृत्त कार्मिक के रूप में भारत सरकार के ग्रेजुटेड आफ ग्रेजुटी एक्ट-1972 के अन्तर्गत प्रस्तुत ग्रेजुटी के दावे के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या-ए-50704/2017 देवेन्द्र नाथ राय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य को न्यायालय (समन्वयक) करते हुये पारित निर्णय दिनांक 17.01.2020 के विरुद्ध विशेष अपील ग्रेजुटेड की गयी है, क्योंकि प्रथमतः निर्णय दिनांक 17.01.2020 अभिकरण, गाजीपुर में ग्रेजुटेड आफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 की प्रयोज्यता के संदर्भ में एक्ट की धारा-1(3) (सी) सहपठित धारा-2(म) के संगत अनिवार्य प्रावधानों की अन्तर्द्वी करने हुये उक्त धाराओं के विपरीत पारित किया गया है तथा आदेश में अभिकरण गाजीपुर में 15 कार्मिक (जिनमें प्रथमतः ग्रेजुटी एक्ट में अनाच्छादित 12 विभागीय कार्मिक सम्मिलित हैं) को ग्रेजुटी एक्ट की प्रयोज्यता के संदर्भ में कावेरत मानते हुये ग्रेजुटीपूर्व निष्कर्ष दिया गया है।	विचारणीय	